



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1941 (श10)

(सं० पटना 758) पटना, सोमवार, 1 जुलाई 2019

सं० 9/सै०-1-पंचायती राज-14/2019-557(9)रा०/  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

21 जून 2019

**विषय:-** भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत अंतरजिला एवं अंतराज्यीय सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) को छोड़कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का प्रबंधन एवं अनुरक्षण पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज संस्थाओं यथा-ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन अंतरजिला एवं अंतराज्यीय सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) को छोड़कर शेष अन्य सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) को पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज संस्थाओं यथा-ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। संविधान की 11वीं अनुसूची के मद सं०-13 में सड़के, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य सम्बद्ध साधन के संबंध में पंचायतों को जिम्मेवारी सौंपे जाने का उल्लेख है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के आलोक में अधिनियमित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-22 (IX) (3), धारा-47 (12) (iii) तथा धारा 73 (21) (ज) द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को नौका, फेरी और जलमार्ग के अनुरक्षण एवं जिला परिषद् को ग्रामीण पुल, तालाब, घाट, कुओं, नहर या नाली का अनुरक्षण एवं नियंत्रण के दायित्व दिये गये हैं।

उपर्युक्त के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का प्रबंधन, नियंत्रण एवं अनुरक्षण का दायित्व पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न स्तर की पंचायत को निम्न रूप से हस्तांतरित किया जाता है :-

(1)	क्रम सं०	पंचायती राज संस्था	बंदोबस्ती की शक्ति
	1	ग्राम पंचायत	रुपया 50,000/- (पचास हजार) तक
	2.	पंचायत समिति	रुपया 1,00,000/- (एक लाख) तक
	3.	जिला परिषद्	रुपया 5,00,000/- (पाँच लाख) तक

(2) अंतरजिला एवं अंतर्राज्यीय सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का संचालन पूर्व की भांति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण के अधीन किया जाता रहेगा।

(3) भूमि का स्वामित्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही रहेगा। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को केवल उक्त भूमि पर अवस्थित सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का उपयोग करने संबंधी प्रशासनिक अधिकार होगा।

(4) यदि भूमि पर अवस्थित सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का उपयोग बंद हो जाती है, तो भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपयोग हेतु वापस हो जायेगी।

(5) भूमि से संबंधित सम्पूर्ण विवरणी तथा राजस्व अभिलेख का संधारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अंचल कार्यालयों द्वारा एक अलग पंजी संधारित कर किया जायेगा। अंचल अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन में हो, जिस प्रयोजन में हस्तान्तरण के पूर्व हो रहा है तथा उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

**आदेश:—** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्याक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्ता को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
प्रत्यय अमृत,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 758-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>